



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 4, 1968 (वैशाख 14, 1890)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 1968 (VAISAKHA 14, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 11 अप्रैल 1968 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 11th April, 1968 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subjects
64	No. 55-ITC(PN)/68, dated 5th April, 1968	.. Ministry of Commerce	Import Policy for Newsprint—Printing and Writing Paper (excluding laid marked paper) which contains Mechanical wood pulp amounting to not less than 70 per cent of fibre contents—S. No. 44/V. for the year April, 1968—March, 1969.
65	No. 56-ITC (PN)/68, dated 8th April, 1968	.. Do.	Errata No. (I)—Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 58-ITC(PN)/68, dated 8th April, 1968	.. Do.	Import Policy for the year April, 1968—March, 1969—Errata No. 2.
66	No. 57-ITC (PN)/68, dated 8th April, 1968	.. Do.	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1968.
67	No. 59-ITC (PN)/68, dated 11th April, 1968	.. Do.	Import Policy for the year April, 1968—March, 1969.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय सूची (CONTENTS)

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

317

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

461

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	31	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	211
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	359	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	349
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 2—एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	165
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	55
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	925	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	147
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2047	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	79
		पूरक संख्या 18—	
		20 अप्रैल 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	589
		30 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	601

	Page		Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	317	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	247
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	461	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	211
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	31	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	349
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	359	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	165
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	55
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	147
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministries of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	925	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	79
		SUPPLEMENT No. 18—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 20th April 1968	589
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 30th March 1968	601

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अप्रैल 1968

सं० 1/1(2) 68-ए० एन० एल०—गृह मंत्रालय की दिनांक 12-1-1968 की अधिसूचना सं० 1/1(2)/67—ए० एन० एल० (i) के अनुसार, राष्ट्रपति लक्कादीव, मिनिक्कोय और अमिनदिवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिये, गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति में, निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 31 मार्च 1969 तक की अवधि के लिये सहर्ष पुनः नामांकित करते हैं :—

आन्दोथ के श्री के० नल्लकोय अमीनी के श्री मेलापुरा अण्डार मिनीकोय के श्री डड्डयू० हुसैन अली कवरसी के श्री के० सैयद मुहम्मद कलपेनी के श्री मूसाकाफडे युसफ ।

अ० द० पांडे, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1968

संकल्प

सं० 25-5/67-एल० डी०-1 (i)---खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 25-5/66-एल० डी०-1 दिनांक 29 जून, 1967, संकल्प सं० 25-5/67-एल० डी०-1 दिनांक 6-2-68 के साथ पठित, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हरेन्द्र नाथ मजुमदार, पश्चिमी बंगाल के पशु पालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के तत्कालीन मन्त्री के स्थान पर केरल के कृषि और विद्युत मन्त्री, श्री एम० एन० गोविन्दन नायर को गौरक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्न को भेजी जाये : 1. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर, कृषि और

विद्युत मन्त्री केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम, 2. समस्त राज्य सरकारें संघक्षेत्र, 3. लोक सभा सचिवालय, 4. राज्य सभा सचिवालय, 5. प्रधान मन्त्री सचिवालय, 6. मन्त्री मण्डल सचिवालय, 7. अध्यक्ष, गौरक्षा समिति, नई दिल्ली, 8. गौरक्षा समिति के समस्त सदस्य, 9. सचिव गौरक्षा समिति, 10. सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति, 11. केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्, नई दिल्ली-11, 12. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

संकल्प

सं० 25-5/67-एल० डी०-1 (ii)---खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 25-5/66-एल० डी०-1, दिनांक 29 जून, 1967, संकल्प सं० 25-5/67-एल० डी०-1, दिनांक 20 दिसम्बर, 1967 के साथ पठित, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राम चन्द्र विकल, तत्कालीन वन एवं पशु पालन मन्त्री, उत्तर प्रदेश के स्थान पर श्री प्रेमजी भाई थैकर, राजस्व मन्त्री गुजरात सरकार को गौरक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्न को भेजी जाए : 1. श्री प्रेमजी भाई थैकर, राजस्व मन्त्री, गुजरात सरकार, अहमदाबाद, 2. समस्त राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र, 3. लोक सभा सचिवालय, 4. राज्य सभा सचिवालय, 5. प्रधान मन्त्री सचिवालय, 6. मन्त्री मण्डल सचिवालय, 7. अध्यक्ष गौरक्षा समिति, नई दिल्ली, 8. गौरक्षा समिति के समस्त सदस्य, 9. सचिव गौरक्षा समिति, 10. सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति, 11. केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्, नई दिल्ली-11, 12. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

एस० जे० मजुमदार, अतिरिक्त सचिव

(भा० क० प्रनु० परि०)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1968

सं० 26 (1)/67-सी० डी० एन० (1)—डा० पी० सी० रहेजा, जो कि इस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 26 (1)/67-सी० डी० एन० (1), दिनांक 6 अगस्त, 1966, के जरिये खाद्य तथा कृषि मन्त्री द्वारा कृषि अनुसन्धान के लिए स्थायी समिति

के सदस्य में मनोनीत किये गये थे, छः मास से अधिक की अवधि के लिए (मिनस्वर, 1967 से विदेश चले गये हैं। इस कारण, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के नियम 77, जिसे नियम 11(ए) के साथ पढ़ा जाये, के उपबन्धों के अन्तर्गत वे कृषि अनुसन्धान के लिए स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

पी० एस० हरीहरन, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 18th April 1968

No. 1/1(2)68-ANL.—In pursuance of para 2(iii) of Ministry of Home Affairs Notification No. 1/1(2)67-ANL(i) dated 12th January 1968 the President is pleased to renominate the following non-official members to the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs, for the Union Territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands for the period upto March 31, 1969 :—

1. Shri K. Nallakoya of Androth.
2. Shri Melapura Andar of Amini.
3. Shri W. Hussain Ali of Minicoy.
4. Shri K. Syed Mohammed of Kavaratti.
5. Shri Moosakakada Yusuf of Kalpeni.

A. D. PANDE, Jt. Secy.

New Delhi-11, the 24th April 1968

No. 7/33/68-P.H.—On his re-employment, Lt. Col. L. V. Hermon took over as Commandant 3rd Battalion, Central Reserve Police, Ajmer on the forenoon of the 1st April, 1968.

G. BALAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 20th April 1968

RESOLUTION

No. 22(13)/68-OR.—The Government of India have decided to set up a Commission under the Commissions of Inquiry Act, 1952, consisting of the following :—

Chairman

Shri Manohar Pershad.

Members

Shri N. V. Modak.

Shri K. R. Bhide.

Dr. M. G. Krishna.

2. The terms of reference of the Commission will be as follows :—

- (i) to determine the correct facts of the contamination with oil of the river Ganga near and downstream of the Barauni Refinery during the last week of February (or earlier) and first week of March, 1968;
- (ii) to determine to what extent the Barauni Refinery has been responsible for the happenings;
- (iii) to recommend the steps that must be taken to prevent the recurrence of such happenings in the future;
- (iv) to advise on whether there has been any negligence or carelessness on the part of the Refinery management and staff in the discharge of their prescribed duties;
- (v) arising out of (iv) to recommend the further action, if any, that must be taken;

(vi) to report on the loss or damage to the public caused by the pollution of the river and to recommend what, if any, restitution the Indian Oil Corporation should make in that connection to those adversely affected;

(vii) generally, to report on any other matter that is relevant, in the opinion of the Commission.

3. The Commission will be assisted by special consultants wherever necessary and desired by it.

4. The Commission will devise its own procedures. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of Government of India will furnish such information and render such assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that the Government of Bihar and all others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Commission.

5. The Commission will submit its report within a period of 3 months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, Government of Bihar and all others concerned.

E. N. MANGATRAI, Special Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 15th April 1968

No. 14-4/68-RIC.—The President is pleased to appoint Shri Y. P. Bali, Assistant Commissioner, Soil Conservation, Ministry of Food, Agriculture (Department of Agriculture) as Project Officer in the Resources Inventory Centre in a temporary capacity with effect from Friday the 5th April, 1968 afternoon, until further orders.

V. S. NIGAM, Under Secy.

New Delhi, the 24th April 1968

RESOLUTION

No. 25-5/67-LD-1(i).—In partial modification of Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Department of Agriculture) Resolution No. 25-5/66-LD-1 dated the 29th June, 1967 read with Resolution No. 25-5/67-LD-1 dated 6th February, 1968, Shri M. N. Govindan Nair, Minister for Agriculture & Electricity, Kerala is appointed as member of the Committee on Cow Protection in place of Shri Harendra Nath Mozumdar, the then Minister of Animal Husbandry & Veterinary Services, West Bengal.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. Shri M. N. Govindan Nair, Minister for Agriculture & Electricity, Kerala.
2. All State Governments/Union Territories.
3. Lok Sabha Secretariat.
4. Rajya Sabha Secretariat.

5. Prime Minister Secretariat.
6. Cabinet Secretariat.
7. The Chairman, Committee on Cow Protection, New Delhi.
8. All Members of the Committee on Cow Protection.
9. Secretary, Committee on Cow Protection.
10. Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti.
11. C.C.G., New Delhi.
12. I.C.A.R., New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

RESOLUTION

No. 25-5/67-LD-I(ii).—In partial modification of Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) Resolution No. 25-5/66-LD-1 dated 29th June, 1967 read with Resolution No. 25-5/67-LD-1 dated 20th December, 1967 Shri Premjibhai Thacker, Minister for Revenue, Government of Gujarat is appointed as Member of the Committee on Cow Protection in place of Shri Ram Chandra Vikal, the then Minister of Forests and Animal Husbandry, Uttar Pradesh.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to:—

1. Shri Premjibhai Thacker, Minister for Revenue, Government of Gujarat, Ahmedabad.
2. All State Govts./U.Ts.
3. Lok Sabha Secretariat.
4. Rajya Sabha Secretariat.
5. Prime Minister Secretariat.
6. Cabinet Secretariat.
7. The Chairman, Committee on Cow Protection, New Delhi.
8. All Members of Committee on Cow Protection.
9. Secretary, Committee on Cow Protection, New Delhi.
10. Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti.
11. C.C.G., New Delhi.
12. I.C.A.R., New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

Indian Council of Agriculture Research

New Delhi, the 24th April 1968

No. 26(1)/67-CDN(I).—Dr. P. C. Raheja who had been nominated by the Minister of Food and Agriculture as a member on the Standing Committee for Agricultural Research vide this Ministry's Notification No. 26(1)/67-CDN (1), dated the 6th August, 1966, has gone abroad in September, 1967 for a period of more than six months. He has thereby ceased to be a member of the Standing Committee for Agricultural Research under the provisions of Rule 77 read with Rule 11 (a) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, the 19th April 1968

RESOLUTION

No. 5-TH.I(35)/67.—With the objective of providing the Hotel Industry in the country with specialised source of financial assistance, it is hereby decided to sanction a scheme for the grant of loans for the construction of hotels of the requisite standard, and for the renovation, expansion and improvement of existing hotels on the approved list of the Department of Tourism to the requisite standard. Assistance shall be rendered in the form of interest bearing loans for the implementation of hotel projects, under the Hotel Development Loan Instructions attached (Annexure 'A').

Applications for the grant of loans under these instructions will be considered by a Board which shall consist of the following:—

Chairman

1. Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation.

Members

2. Representative of the Ministry of Finance, (Department of Expenditure).
3. Representative of the Ministry of Works, Housing & Supply.

Member-Secretary

4. Director General of Tourism.

The Board shall satisfy itself that the security offered by the applicant company is sufficient and in terms of the prescribed instructions shall have powers to make recommendations to the Ministry for sanction of loans. Loans in excess of Rs. 25 lakhs shall be sanctioned with the approval of the Government of India, in the Ministry of Finance.

The Board may require the company to undergo a special audit of their accounts by the Comptroller & Auditor General of India or his nominee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. C. DUTT, Secy.

ANNEXURE 'A'

INSTRUCTIONS FOR GRANT OF LOANS FOR HOTEL DEVELOPMENT

I. Objective

To provide to the Hotel Industry in the country a specialised source of financial assistance in the shape of interest bearing loans for the implementation of hotel projects.

Explanation

Hotel project means:

- (1) the construction of hotels of the standard suitable for occupancy by foreign tourists; and includes
- (2) renovation and expansion of existing hotels on the approved list of the Department of Tourism with a view to improving their existing standards and/or to providing additional facilities.

II. Constitution and powers of the Board

A Board will be set up to consider applications for the grant of loans to the Hotel Industry under these instructions. It shall satisfy itself that the security offered by the applicant company is sufficient in accordance with these instructions and shall make its recommendations on the applications to the Ministry of Tourism and Civil Aviation. The Ministry shall have powers to sanction the loans provided that loans exceeding Rs. 25 lakhs shall require the approval of the Government of India.

The Board may also require the company, to undergo a special audit of their accounts by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee.

The Board shall consist of the following:—

Chairman

- (1) Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation.

Members

- (2) Representative of the Ministry of Finance, (Department of Expenditure).
- (3) Representative of the Ministry of Works, Housing & Supply.

Member-Secretary

- (4) Director General of Tourism.

III. Eligibility

(1) A public limited company or a private limited company is eligible for loans under these instructions provided the hotel project for which the loan is sought has the prior approval of the Department of Tourism.

(2) The project should be financially sound and the applicant company should adduce evidence before the Board as regards its capacity to raise not less than 33.1/3% of the total estimated cost of the project from its own or other resources.

(3) The hotel project should be located in an area of tourist importance as may be approved by the Board from time to time. The opinion of the Board in this respect will be final.

(4) The project should be of a size and standard considered suitable for the area in which it is located so that the cost of its operation is not uneconomical and as a minimum requirement should conform to the criteria prescribed for hotels in the 3 star category.

(5) The applicant company should be agreeable to accept and abide by the regulatory conditions for the operation of hotels prescribed by the Department of Tourism from time to time.

IV. Quantum of Loan

1. *New constructions*: Up to a maximum of 66.2/3% of the value of the fixed assets of the hotel project namely land, building and other immovable assets as specified in Annexure 'B'.

Purchase and conversion of buildings into hotels will be treated as new construction for granting loans, provided the applicant company satisfies the Board by offering the building(s) covered by the application and/or the applicant company's other immovable assets as securities.

2. *Expansion/Renovations*: Up to a maximum of 50% of the cost to be incurred, as examined, assessed and agreed to by the Board.

V. Terms and Conditions

1. Security for Loans.

(a) The applicant company shall furnish securities to the value equal to 133.1/3% of the amount of the loan proposed to be sanctioned in its case or of the amount of the loan remaining unpaid by it, as the case may be, throughout the period of the currency of the loan.

(b) The equity-debt ratio should not exceed 1:2. Equity will comprise paid-up equity capital, preference share capital of redemption period of 12 years and more, and free reserves including Development Rebate Reserve. Loans will include preference share capital or redemption period of less than 12 years, secured loans including debentures for purchase of fixed assets, and other secured or unsecured loans, whether or not for purchase of fixed assets, but *not* loans from banks for working capital purposes against hypothecation of stocks of raw materials, stores, tools etc.

(i) *New Constructions*: In the case of loans for construction of hotels as contemplated by explanation (1) of para I, the applicant company shall furnish to the satisfaction of the Board security in the shape of mortgage or unencumbered landed property and buildings thereon and other unencumbered fixed assets over which the applicant company has clear title.

(ii) *Renovation and Expansion*: Loans will be secured on the basis of a guarantee bond from a first-class scheduled bank/insurance company guaranteeing repayment of the entire loan amount and its interest, or other sufficient unencumbered securities including mortgage of existing hotel buildings, fixed assets or other immovable property. Where the applicant company has furnished scheduled Bank/insurance company's guarantee bond as security for the repayment of the loan amount together with interest prescribed in these instructions and where the aforesaid document covers the entire repayment period of the loan, then the security so offered shall be of the value equal to 100% of the amount of loan.

2. Review of securities

The Board shall conduct a review of the security in respect of each loan at least once in every three years from the date of the grant of loan. The Board may, however, conduct such a review at any time it likes in respect of any security furnished, where it considers it necessary to do so to effectively safeguard the loan advanced. If this value is found to be less than the security required, the borrowing company shall be asked to make up the shortfall immediately by furnishing additional security.

3. Government nominee on the Board of Directors of the borrowing company

The Government will nominate Directors not exceeding two on the applicant company's Board of Directors for so long as any sums remain due and outstanding in respect of the loan from the applicant company to the Government. The Directors so nominated shall not be required to hold any qualification shares, shall not be removable by the applicant company and shall have the right to attend and address the applicant company's annual and other general meetings.

Both the Directors shall exercise all the rights of a Director exercisable under the law and under the Articles of Association of the applicant company.

4. The applicant company shall, if necessary, amend their Articles of Association to provide for the requirements mentioned above, to give effect to the conditions mentioned in para V(3).

5. The applicant company shall furnish all information regarding their day to day working which may be called for either by the Board or by the Directors nominated by the Government on its Board of Directors.

The Government's nominee(s) on the Board may at any time call upon the applicant company to submit returns or statements of the number and/or names of foreign tourists lodged in its hotel during any specified period and the rents etc. charged from them and the applicant company shall forthwith furnish detailed information asked for to the Government's nominee(s) on the Board. It shall also likewise be a condition of the application that the applicant company shall honour the requisition of the Director General of Tourism or any person authorised by him for accommodating foreign tourists in the applicant company's hotel at any time after giving notice. Defaults in complying with these conditions will be dealt with as provided for in Para IX, or otherwise as may be decided by the Board.

6. Completion of the Project

The project for which the loan is to be taken will have to be completed within the period stipulated by the Board. Non-completion of the project by the target date specified in the agreement, shall be treated as a default in terms of Para IX. If, in exceptional circumstances, the completion of the project is not possible within the specified date, the Board may, in consultation with the Ministry of Finance, and after satisfying itself as to the validity of the justification, decide to extend the date of completion of the project.

7. Insurance

The property and assets offered by the applicant company and accepted by the Board as security under these instructions shall be insured to cover risks arising from theft, fire, flood, lightning, riots for an amount determined by the Board having regard to the quantum of loan and interest thereon, or for any higher amount that the applicant company may decide, and the insurance policies assigned to the President of India. It shall also be the duty of the applicant company to maintain the aforesaid mortgage assets in the best condition to the satisfaction of the Board.

VI. Mode of Payment

(a) The loan sanctioned under these instructions shall be paid to the applicant company by the Board in instalments, each instalment to be determined having regard to the value as certified by the competent authority acceptable to the Board, e.g. District Magistrate/P.W.D./Chartered Accountants etc. of the mortgage property and other assets as well as the value of the new constructions or the expenditure incurred by the applicant company in respect of renovations etc. at the relevant point of time.

(b) The applicant company shall be required to submit a utilisation certificate in the prescribed form duly verified by their auditors in respect of each instalment before the next instalment is authorised for payment.

VII. Rate of Interest and its Payment

The rate of interest on the loans sanctioned under these instructions will be the rate charged by the Government from industrial undertakings from time to time (at present 6½-7% per annum) depending on the duration of the loan. In case the applicant company makes any default either in the payment of the instalment of the loan amount and/or of the interest on the due dates mentioned below, it shall be liable to pay interest at 2½% per annum higher than the rate at

which the loan has been advanced both in respect of the instalment of the loan amount and of the interest.

Interest on the loan will be payable on a half-yearly basis commencing from the date on which the amount of the loan is drawn by the applicant company, until the loan is repaid in full.

VIII. Repayment of Principal

New Construction.—The loan will be repayable in eighteen half-yearly instalments over a period of 9 years, the first instalment being due after 3 years from the date on which the first instalment of the loan is made available.

Expansion/Renovaton : The loan will be repayable in fifteen (15) half-yearly instalments over a period of 7½ years (seven and half years) the first instalment to be paid after one year from the date on which the first instalment of the loan is made available.

It will however, be open to the applicant company to commence repayment of the loan during the period of moratorium mentioned, or to repay the entire loan with interest at any time before the end of the periods of loan prescribed above.

IX. Defaults

If any default is committed by the applicant company either in the payment of the interest or repayment of the loan instalments or in complying with any of the terms and conditions of the loan then the Board may, at its discretion and depending on the merits of the case deal with the default in any one or more of the following ways :—

- (i) Interest will be charged at a rate 2½% higher than the normal rate of interest on the balance of payments due on the loan.

The rate of interest will be again reduced to normal with effect from the date the arrears have been paid up and payments are regular.

- (ii) The Board shall not pay further instalments of the loan and shall require and applicant-company to deposit the entire amount of loan with interest with the Government, within 4 months of the date of default.
- (iii) In the event of 3 successive defaults in the payment of instalments/interest taking place, the mortgage will be foreclosed.
- (iv) The business of the borrower company may be taken over and its business run by the Government or by any nominee or any agency of the Government specifically designated for this purpose.

X. The applicant company shall before the drawal of the loan in terms of these instructions execute a loan agreement and a mortgage deed in the prescribed form.

XI. Accounts of these loans should be maintained by the Department of Tourism which shall also watch their recoveries and the fulfilment of the terms and conditions of the loan.

Applications for loans shall be submitted in the prescribed proforma (Annexure 'C') with supporting certificates wherever necessary to Secretary, Hotel Development Loans Board, Department of Tourism, Transport Bhavan, 1-Parliament Street, New Delhi-1.

ANNEXURE 'B'

LIST OF FIXED ASSETS IN THE HOTEL INDUSTRY

1. Land.
2. Building, including sanitary wares and fittings.
3. Plant and Machinery (including freight insurance, import duty sales tax, clearing, loading, unloading and transport charges) viz.
 - (i) Air conditioning plant.
 - (ii) Refrigerators, water cooler and ice making plant.
 - (iii) Laundry plant.
 - (iv) Walk-in-type refrigerator and deep freeze cold storage.
 - (v) Bakery equipment.
 - (vi) Lifts (electrical conveyers).
 - (vii) Hot water supply equipment including boilers.
 - (viii) Water softening plant.
 - (ix) Sound system.

4. Misc. fixed assets,

- (i) Tube well and pump.
- (ii) Installed kitchen equipment.
- (iii) Sewage disposal plant or apparatus.
- (iv) Health club and workshop equipment.
- (v) Fixed carpeting.

ANNEXURE 'C'

APPLICATION FOR GRANT OF LOAN FOR HOTEL PROJECTS

Part A

1. Name and address of the company.
2. (a) Whether public limited or private limited company.
2. Authorised Capital.
3. Issued, subscribed and paid-up capital.
4. Number of hotels, if any, already owned by the company, indicating separately in respect of each hotel its bed capacity, its original cost and depreciated cost as per the books, its insured value and market value. The market value should be supported by a certificate of valuation recognised under the provisions of Estate Duty Act/Wealth Tax Act.
5. In the case of companies in existence for three years or more copies of audited balance sheets and profit and Loss Accounts for the last three years (indicating working results, assets and liabilities and dividend, if any, declared) may be furnished. In the case of others, necessary information to the extent available may be furnished.
6. Particulars of loan(s) if any already granted to or applied for by the Company to banks and other financial institutions.
 - (a) Amount(s) of loan, date of grant and rate of interest.
 - (b) Hotels against which the loan(s) was/were granted. Give full particulars of the assets against which the loan(s) is secured.
 - (c) Repayment(s) commenced or to commence from which date and to be made in how many instalments.
 - (d) Whether there has been in the past any default in the payment of instalments of either principal or interest, if so, on how many occasions, and for what reasons.
 - (e) Outstanding Balance of loans if any.
7. Full particulars of :—
 - (a) Hotel now proposed to be built.
 - (b) Location : Does the company own the land or was it obtained on lease ? Please give particulars.
 - (c) Total cost of the hotel project indicating the cost of each of its components, including that of the foreign exchange element in the overall expenditure. Copies of the site plan and architectural designs should be furnished together with the names of the architects and copies of agreements entered into with architects.
 - (d) Amount of loan now required from the fund.
 - (e) Have arrangements been made to provide the balance of funds needed for the completion of the project. If so, please provide documentary evidence.
8. What security, in addition to the mortgage of the hotel is the company prepared to offer, if so required and pending the building of the hotel what interim security is proposed to be furnished ?
9. Whether the company is aware of the terms of the Government of India 'Hotel Development Loan Instructions' on which loans are granted for hotel development and if so, whether the company is prepared to accept them in their entirety.
10. (a) Anticipated working results in future, and
 - (b) Whether such results fully establish the possibility of the company repaying the loan within the period of amortisation without any difficulty ?

To be signed by the Managing Director or other authorised official of the company.

Part B

(To be filled by the Director General of Tourism)

1. Is the Director General of Tourism satisfied that the particulars furnished above by the company are correct to the extent that they can be verified?

2. Is the Director General of Tourism generally satisfied after making such consultation as he deems necessary from his Technical Officer, that the hotel project is suitable for the purpose for which it is intended?

3. Does the Director General of Tourism recommend the grant of the loan applied for by the Company? Is he satisfied that there is a reasonable prospect of the company being able to repay the loan within the period of amortisation and the security offered by the Company including the interim security is good and sufficient?

4. In case the company desires any modification of the usual terms to what extent does the Director General of Tourism recommend them and on what precise grounds?

5. Has the Director General of Tourism any special comments to offer on the proposal?

To be signed by the Director
General of Tourism or other
authorised officer of the Director
General of Tourism.

Part C

Decision of the Hotel Development Loan Board.

To be signed by Secretary,
Hotel Development Loan Board

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 28th March 1968

RESOLUTION

No. 14/35/64-FC.—In pursuance of the decision to enquire into the working of the existing procedures for certification of Cinematograph films for public exhibition in India and allied matters, the Government of India have decided to set up an Enquiry Committee on film Censorship composed as follows :—

Chairman

Shri G. D. Khosla, I.C.S. (Retired), formerly Chief Justice, Punjab.

Members

1. Shri Lok Nath Misra, M.P. (Rajya Sabha).
2. Shri M. P. Bhargava, M.P. (Rajya Sabha).
3. Shri S. K. Vaishampayan, M.P. (Rajya Sabha).
4. Shri P. Venkatasubbaiah, M.P. (Lok Sabha).
5. Shri Nath Pai, M.P. (Lok Sabha).
6. Shri R. D. Bhandare, M. P. (Lok Sabha).
7. Smt. Sharda Mukherji, M.P. (Lok Sabha).
8. Shri Karni Singh, M.P. (Lok Sabha).

9. Shri K. A. Abbas.
10. Shri R. K. Narayan.
11. Padmashri Smt. Nargis.
12. Shri Tapan Sinha.
13. Shri A. V. Meiyappan.
14. Shri Ramesh Thapar.
15. Shri Umashankar Jethalal Joshi.
16. Chairman, Central Board of Film Censors.
17. Deputy Secretary Films—Member-Secretary.

The terms of reference

The terms of reference of the said Committee will be :

1. To study the effect of films exhibited in public on the people in the context of changing the needs of society.
2. To enquire into the state of films in India in regard to their artistic content and healthy mass appeal in relation to the existing regulatory procedures.
3. To study the working of existing laws, machinery and procedures for the certification of Indian and foreign cinematograph films for public exhibition in the country.
4. To recommend, on the basis of the above studies, measures for improvement in the existing censorship laws, machinery and procedures with a view to;
 - (a) enabling the Indian film to develop into an effective creative medium keeping in tune with the contemporary trends in social conduct and practices and responsive to the emotional and intellectual needs of the people.
 - (b) promoting between the film industry and the regulatory organisation a close understanding, which would be conducive to the production/exhibition of films of artistic excellence, high entertainment value and accepted moral standard.
 - (c) preventing the production/exhibition of films which offend against public taste.

The Committee will meet as often as considered necessary. The headquarters of the Committee will be in New Delhi, but the Committee may visit such other places as considered necessary for a proper appraisal of the subject.

5. The Committee will evolve its own procedure.

6. The Committee will commence work as soon as possible and submit its report to Government by 31st July, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all members of the Committee, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, All Ministries.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

A. MITRA, Secy.